

भारत की मौद्रिक नीति की भावी तैयारी*

माइकल देवब्रत पात्र

नमस्कार!

मुझे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में आमंत्रित किए जाने पर गर्व है, जो स्वतंत्र भारत का एक मंदिर है, जिसका इतिहास स्वतंत्रता से पहले का है। मैं मैडम सौजन्या को उनकी सौम्य दृढ़ता और कुशल प्रबंधन के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से मेरा यहां आना संभव हो पाया। मैं समझता हूँ कि यह अकादमी के मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के चरण IV का 18वां दौर है। यहां के प्रतिभागी पहले ही राष्ट्र की सेवा में 15 से 18 साल लगा चुके हैं और इसलिए, वे अगले 40-50 वर्षों में हमारे देश को विकसित देश बनने के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की खोज में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी ओर देखता है, क्योंकि आप लोक नीति का संचालन करेंगे और राष्ट्र को उसके आकांक्षानुकूल लक्ष्य की ओर ले जाते हुए शासन की चुनौतियों का सामना करेंगे। ऐसा करते समय, आपको संगठनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों के रूप में टेक्टोनिक उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करना होगा। मुझे आशा है कि मेरा व्याख्यान आपके सामने आने वाली यात्रा पर थोड़ा प्रकाश डाल सकेगा।

इसी संदर्भ में मैं आपसे मौद्रिक नीति के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं इसे अगले चालीस से पचास वर्षों के परिप्रेक्ष्य में रखूंगा, ताकि उन अवसरों और चुनौतियों के बारे में कुछ परिप्रेक्ष्य सामने आ सकें, जो भारत को उसके भविष्य की ओर ले जाते समय आपके सामने आएंगी।

* मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, श्री माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया संबोधन। हरेंद्र बेहरा, आशीष थॉमस जॉर्ज से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त संपादकीय सहायता के लिए आभार।

प्रथम सिद्धांत

मौद्रिक नीति के डिजाइन और संचालन को आकार देने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों की चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

सबसे पहले, लोक नीति साधनों के शस्त्रागार में, मौद्रिक नीति को इसकी तीव्र तैनाती के लिए जाना जाता है क्योंकि जिन स्थितियों का सामना इसे करना पड़ता है, उनके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे आम तौर पर अपनी उत्पादक क्षमता के आसपास अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का कार्य सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए, जब कुल मांग या कुल व्यय देश की उत्पादक क्षमता से अधिक हो जाता है, तो असंतुलन विकसित होता है जो आसानी से अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। इन असंतुलनों के पहले संकेत आमतौर पर मूल्य दबाव या मुद्रास्फीति होते हैं। तदनुसार, मौद्रिक नीति कुल मांग को कम करने और इसे उत्पादक क्षमता के साथ संरेखित करने के लिए कार्य करती है। इसी तरह, जब मांग उत्पादक क्षमता से कम हो जाती है, तो अपस्फीति की स्थिति विकसित हो सकती है और इसलिए मौद्रिक नीति को मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बहाल करने के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना पड़ता है।

दूसरा, मौद्रिक नीति को भविष्योन्मुखी होना चाहिए। किसी भी समय, मौद्रिक नीति अधिकारियों के पास लक्ष्य चरों पर उपलब्ध जानकारी पिछड़ी हुई होती है - उदाहरण के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जैसी आर्थिक गतिविधि के माप पर, किसी भी समय उपलब्ध जानकारी आम तौर पर तीन महीने पुरानी होती है, यानी भारत में जनवरी-मार्च से संबंधित; भारत में उपभोक्ता कीमतों पर जानकारी केवल मई के लिए उपलब्ध होती है। इसके अलावा, नीतिगत गति ब्याज दरों की संरचना के माध्यम से परिवर्तनशील और अनिश्चित अंतराल के साथ यात्रा करते हैं - नीतिगत ब्याज दर में परिवर्तन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए उधार दरों में पूरी तरह से परिलक्षित होने में समय लेते हैं। इसलिए, अक्सर ऐसा होता है कि मौद्रिक नीति को अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। इसके अलावा, लक्ष्य चर गतिशील होते हैं और इसलिए, मौद्रिक नीति को आगे बढ़ना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए, यह चलती लक्ष्य चरों के निर्माण को ट्रैक करने और उन्हें सटीक रूप से लक्षित करने के लिए रडार स्क्रीन की तरह सभी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग

करता है। यह कार्य तब और भी जटिल हो जाता है जब उनके अप्रत्याशित भविष्य जैसे कि अगले चालीस से पचास वर्षों में संभावित घटनाक्रम से निपटना पड़ता है। हम अभी वहां पहुंचेंगे।

तीसरा, जैसा कि अर्थशास्त्र के लिए 1969 के नोबेल पुरस्कार विजेता जान टिनबर्गन ने दिखाया, कोई भी नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक कुशल होती है जब वह असाइनमेंट नियम का पालन करती है - यदि नीति ब्याज दर जैसा एक साधन है, तो एक लक्ष्य भी होना चाहिए। इसके बजाय, यदि मौद्रिक नीति बहुत सारे लक्ष्यों से बोझिल है, लेकिन बहुत कम साधनों से भी बाधित है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि साधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा।

चौथा, मौद्रिक नीति को कुछ नियम जैसे व्यवहार के संदर्भ में संचालित किया जाना चाहिए जो इसे समय के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है। इसके बजाय, यदि यह अल्पावधिक ट्रेड-ऑफ का फायदा उठाने के प्रलोभन का शिकार हो जाता है - जैसे अल्पावधि में मुद्रास्फीति नियंत्रण को छोड़ना और संवृद्धि को बढ़ावा देना या जिसे अर्थशास्त्री समय असंगति कहते हैं - तो यह अंततः अपने उद्देश्य से भटक जाएगा क्योंकि अल्पावधिक संवृद्धि की खोज में, मुद्रास्फीति को ऐसे स्तरों तक बढ़ने दिया जा सकता है जो विकास के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

पांचवां, आधुनिक मौद्रिक नीति प्राधिकरणों ने पाया है कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता तब बढ़ जाती है जब इसे नीतिगत कार्रवाइयों के इरादे और इसके लक्ष्यों के संदर्भ में रुख और उन्हें प्राप्त करने के तरीके और समय सीमा के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी संचार द्वारा समर्थित किया जाता है। संचार मौद्रिक नीति को जवाबदेह बनाता है क्योंकि जनता इसके प्रभाव को मापने में सक्षम होती है। यह, बदले में, नीति प्राधिकरण को इसके घोषित इरादे से बांधकर और मध्यम अवधि के लक्ष्यों की कीमत पर अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने में असीमित विवेक को बाधित करके इसे विश्वसनीय बनाता है। वास्तव में, उच्च विश्वसनीयता बड़े नीतिगत परिवर्तनों या यहां तक कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता को समाप्त कर देती है यदि जनता नीति के कल्याणकारी अभिविन्यास में विश्वास करती है। नतीजतन, संचार मौद्रिक नीति के लक्ष्यों के लिए जनता की अपेक्षाओं को

जोड़ने में मदद करता है ताकि नीति निर्माता और सभी हितधारक अपेक्षाओं के एक समान सेट के साथ काम करें। नीति, उसके आचरण और उसके लक्ष्यों के आसपास की अपेक्षाओं में स्थिरता व्यापक आर्थिक स्थिरता को जन्म देती है जो मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए ठोस आधार प्रदान करती है।

भविष्य का आकलन

मौद्रिक नीति का एक अंतर्निहित घरेलू अभिविन्यास होता है। इसलिए, जिस अर्थव्यवस्था में यह काम करती है उसकी विशेषताओं और जिस मार्ग पर आर्थिक गतिविधि के विकसित होने की सबसे अधिक संभावना है, उसकी अच्छी समझ अच्छी मौद्रिक नीति को तैयार करने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में जो समय परिप्रेक्ष्य चुना था, उसके संदर्भ में, पूछने का सवाल यह है: आज हम कहाँ हैं? और यहाँ से हमें कहाँ जाना है?

2023-24 तक, यानी, अभी-अभी बीता वर्ष, भारत वर्तमान विनिमय दरों पर ₹295.4 लाख करोड़ या यूएस\$3.6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। ₹2,07,030 या यूएस\$2,500 की प्रति व्यक्ति आय के साथ, भारत देशों के निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है। यहां तक पहुंचना एक घटनापूर्ण और कठिन यात्रा रही है, जिसे सांख्यिकीविदों ने 'संरचनात्मक विराम' कहा है। पहला विराम 1980 में हुआ, जो आजादी के बाद के उस दौर का अंत था जब जीडीपी वृद्धि औसतन 3.6 प्रतिशत या तथाकथित हिंदू विकास दर थी। यह अंतर्मुखी होने का युग था। 1980 से लेकर 2002 के आसपास दूसरे विराम तक, विकास दर औसतन 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गई क्योंकि भारत खुल गया, व्यापार और पूंजी प्रवाह की बाधाओं को हटा दिया, तीसरा ब्रेक 2020 में महामारी के कारण हुआ। 2002 और 2020 के बीच, उदारीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन के लाभ समेकित हुए और प्रवृत्ति वृद्धि 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गई, लेकिन 2020-21 में जीडीपी में 5.8 प्रतिशत की भारी गिरावट के कारण यह बाधित हो गई। हालांकि, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण और चतुर मैक्रोइकॉनॉमिक नीति समर्थन के सहारे, महामारी के बाद की अवधि में एक मजबूत वापसी हुई है। हालांकि पर्याप्त डेटा बिंदुओं की कमी के कारण यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक और संरचनात्मक बदलाव हो सकता है जो प्रवृत्ति वृद्धि को 8 प्रतिशत से ऊपर ले जा रहा है - जो आज दुनिया की सबसे तेजी

से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 2024 में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि भारत वैश्विक संवृद्धि में लगभग छठा हिस्सा योगदान करने जा रहा है।¹

यह अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत अगले दस वर्षों में प्रति वर्ष 9.6 प्रतिशत की दर से विकास कर सकता है, तो यह निम्न मध्यम आय के जाल से मुक्त हो जाएगा और एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन लाभों को प्रति व्यक्ति आय में परिलक्षित होना चाहिए - मध्यम आय वाले देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति आय स्तर 4516-14,005 अमेरिकी डॉलर और आज विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस स्तर से आगे बढ़ना। हालाँकि, 2047 तक, विकसित देश की सीमा 34,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी।

बाजार में निर्धारित वर्तमान विनिमय दरें अस्थिरता और अजीबोगरीब व्यवहार के अधीन हैं जो उन्हें वास्तविकता से अलग कर देती हैं। इसलिए, राष्ट्रीय मुद्राओं में मापी गई जीडीपी के डीनॉमिनेटर के रूप में उनका अनुप्रयोग क्रॉस-कंट्री तुलना के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। एक वैकल्पिक उपाय क्रय शक्ति समता (पीपीपी) है। यह प्रत्येक देश में वस्तुओं और सेवाओं की एक औसत बास्केट की कीमत है। पीपीपी के साथ, तुलना नाटकीय रूप से बदल जाती है। पीपीपी के संदर्भ में, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 के लिए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पीपीपी के संदर्भ में 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में तब्दील होता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुमान है कि पीपीपी के संदर्भ में, भारत 2048 तक अमेरिका से आगे निकलकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

विक्टर ह्यूगो के शब्दों में कहें तो, किसी देश से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता जिसका समय आ गया हो। जापान का युग 1960 के दशक में शुरू हुआ और 1980 के दशक तक चला। चीन का युग 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जिसने इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। 2010 से भारत का समय आ गया है। भारत को आगे बढ़ाने और अगले दो-तीन दशकों में विश्व नेता के रूप में अपना सही स्थान प्राप्त करने के लिए कई ताकतें एक साथ आ रही हैं।

¹ विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक; 15 जनवरी 2024।

अनुकूलताएं

मौद्रिक नीति के निर्माण में जोखिमों के संतुलन का मूल्यांकन करना एक अच्छा हाउसकीपिंग माना जाता है। कई सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं जो अगले कुछ दशकों में भारत के भविष्य की दृष्टि को आकार देने में मदद कर रही हैं। इन शक्तियों की भूमिका भविष्य की मौद्रिक नीति की स्थापना को प्रभावित करेगी।

सबसे पहले, एक पारंपरिक लाभ है जो भारत की विकास संभावनाओं के पक्ष में जारी रहने की संभावना है। विकास प्रक्रिया मुख्य रूप से पूंजी संचय द्वारा संचालित होती रही है, जो निवेश को संवृद्धि का मुख्य साधन बनाती है। 2010-11 में निवेश दर जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद 2020-21 तक असमान रूप से कम हो गई। हालाँकि, 2021-23 के दौरान यह 31.2 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो गई है और इसमें तेजी के संकेत दिख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत के निवेश को घरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित किया गया है, जिसमें परिवार अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों के लिए संसाधनों के प्रमुख प्रदाता रहे हैं। 2021-23 की अवधि में सकल घरेलू बचत दर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का औसतन 30.7 प्रतिशत रही है। इस प्रकार, कई देशों के विपरीत, भारत को विदेशी संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जो विकास प्रक्रिया में एक छोटी और पूरक भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, इस परिघटना की दर्पण छवि - भुगतान संतुलन में चालू खाता अंतर - 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1 प्रतिशत पर मामूली बना हुआ है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी क्षेत्र को व्यवहार्यता और मजबूती प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, भारत का सकल विदेशी ऋण, जो समय के साथ चालू खाता घाटे का संचय है, सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम है और लगभग पूरी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर से कवर किया जाता है। ऋण सेवा, यानी ब्याज और मूलधन चुकौती एक साथ चालू प्राप्तियों के 7 प्रतिशत से कम है। जहां तक सुपरसेवर्स - परिवारों का संबंध है - वित्तीय बचत से भौतिक बचत की ओर स्विच करने के प्रमाण हैं, जिसमें बाद में परिवारों की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

दूसरा, भारत जिस बढ़ती हुई विकास की राह पर आगे बढ़

रहा है, वह व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी हुई है। महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों द्वारा उत्पन्न ऊपरी दबावों के साथ एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद, और खाद्य आपूर्ति आघातों के छिटपुट हमलों से और भी बढ़ गई, मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास स्वीकार्य दायरे में वापस आ गई है। यह दृढ़ मौद्रिक नीति कार्यों और आपूर्ति प्रबंधन के संचयी प्रभाव को दर्शाता है। वास्तव में, मुख्य मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं है और जो मौद्रिक नीति के लिए सबसे अधिक अनुकूल है, अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध रहकर उम्मीदों को स्थिर किया है और मूल्य दबावों में हाल ही में आई कमी को प्रगति पर काम के रूप में माना है। इसने 2024-25 में मुद्रास्फीति के औसतन 4.5 प्रतिशत और 2025-26 में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मुद्रास्फीति पर काबू पाना उपभोग की स्थिति, निवेश के दृष्टिकोण और बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके भविष्य में निरंतर उच्च संवृद्धि की नींव रखता है।

व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ, वित्तीय स्थिरता विवेकपूर्ण वित्तीय नीतियों और सक्रिय ऑन-साइट पर्यवेक्षण के साथ-साथ ऑफ-साइट निगरानी से सुदृढ़ हो रही है, जो सुपटेक, बड़े डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा अभ्यासों का उपयोग करती है। भारत का वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से बैंक आधारित है। बैंकिंग प्रणाली में सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) मार्च 2018 में अपने चरम से लगातार गिरकर मार्च 2024 तक कुल आस्तियों का 2.8 प्रतिशत रह गई हैं। प्रावधानों के लिए समायोजित, शुद्ध एनपीए सिर्फ 0.6 प्रतिशत है। पूंजी और तरलता बफर विनियामक मानदंडों से काफी ऊपर हैं। लाभप्रदता अधिक है और इस चक्र ने ऋण वृद्धि का समर्थन किया है। क्रेडिट जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए दबाव परीक्षण से पता चलता है कि बैंक गंभीर दबाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से ऊपर रहेंगे।

समष्टि आर्थिक स्थिरता का एक अन्य पहलू चालू राजकोषीय सुदृढ़ता है। नतीजतन, सामान्य सरकारी ऋण जो मार्च 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 81.6 प्रतिशत होने का अनुमान

है, आईएमएफ द्वारा इस दशक के अंत तक घटकर 78.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। हमारे अनुमानों से पता चलता है कि यदि विनिर्माण के सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में श्रम बल को फिर से कौशल प्रदान करने/अपस्किंग करने, डिजिटलीकरण में निवेश करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने पर व्यय बढ़ाया जाता है, तो सामान्य सरकारी ऋण 2030-31 तक सकल घरेलू उत्पाद के 73.4 प्रतिशत तक और भी कम हो जाएगा² यह आईएमएफ के अनुमानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2028 में 116.3 प्रतिशत और उभरते और मध्यम आय वाले देशों के लिए 78.1 प्रतिशत तक ऋण अनुपात दिखाते हैं।

भारत की अनुकूल जनसांख्यिकी गतिशीलता से एक शक्तिशाली विकास त्वरक उभरता है। भारत की जनसंख्या, जिसे कभी माल्थसियन अभिशाप माना जाता था, अब अंतर-कालिक परिप्रेक्ष्य में इसकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है, खासकर जब बाकी दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है और आबादी घट रही है। आज, दुनिया में हर छठा कामकाजी उम्र का व्यक्ति भारतीय है। 28 वर्ष की औसत आयु के साथ, कुल जनसंख्या में कामकाजी आयु वर्ग का हिस्सा 2050 के दशक के मध्य तक बढ़ता रहेगा, जिससे आय और बचत में वृद्धि के मामले में समान लाभ होगा। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तीन दशकों से अधिक समय तक रहने की उम्मीद है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

भारत की डिजिटल क्रांति विकास को बढ़ाने वाला एक और कारक है। भारत परिवर्तनकारी बदलाव के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में विश्व में अग्रणी बन रहा है। जे ए एम की त्रिमूर्ति - जन धन (बुनियादी नो-फ्रिल्स खाते); आधार (सार्वभौमिक विशिष्ट पहचान); और मोबाइल फोन कनेक्शन - औपचारिक वित्त के दायरे का विस्तार कर रहे हैं, तकनीकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लक्षित करने में सक्षम बना रहे हैं। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), एक ओपन-एंडेड सिस्टम है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में सक्षम बनाता है, जो अंतर-बैंक पीयर-टू-पीयर और व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन को सहजता से

² पात्र एम.डी., बेहरा, एस., बेहरा, एच., बर्नजी, एस., पाधी, आई. और सूद, एस. (2024)। विकास संगत राजकोषीय समेकन का स्वरूप आरबीआई बुलेटिन, फरवरी।

आगे बढ़ा रहा है। भारत में भुगतान प्रणाली 24x7x365 आधार पर काम करती है। ऑफलाइन भुगतान, फीचर फोन के माध्यम से भुगतान और संवादात्मक भुगतान जैसी कार्यक्षमताएँ शामिल की गई हैं। यूपीआई का अंतरराष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रतिकूलताएं

भारत की संवृद्धि संबंधी महत्वाकांक्षाओं की दिशा में प्रगति को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या जिन्हें मौद्रिक नीति विश्लेषण में नकारात्मक जोखिम कहा जाता है। इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना मौद्रिक नीति के संचालन का परीक्षण होगा क्योंकि भारत अपनी नियति की तलाश में आगे बढ़ रहा है।

जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की कुंजी सकल मूल्य वर्धन में श्रम बल के योगदान को बढ़ाने में है। नौकरी सृजन और उच्च कौशल के लिए पुरस्कारों में हाल के सुधारों के बावजूद, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के हिस्से - जो कौशल निर्माण के प्रतिफल को संदर्भित करता है - भारत के श्रम का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कम है। किसी विशिष्ट नौकरी के लिए उपयुक्त कौशल के मामले में, केवल 51 प्रतिशत ही रोजगार योग्य हैं, जिससे नौकरी की आवश्यकताओं और तकनीकी बदलाव के अनुरूप कार्यबल को फिर से कुशल और उन्नत करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।³ 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और यह रोजगार के औपचारिकरण के विस्तार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, भारत कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के मामले में निचले पायदान पर है। महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती है, जिसके लिए कामकाजी महिलाओं के पक्ष में सामाजिक मानकों की आवश्यकता है, मसलन - शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों में विविधता को प्रोत्साहित करना; कार्यस्थलों पर लचीले कार्य घंटे और महिलाओं के लिए अनुकूल नीतियां और सुविधाएं; और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना।

एक और बड़ी चुनौती उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण है। भारत में बुनियादी ढांचे में प्रति व्यक्ति निवेश 2015 के स्थिर डॉलर में 90 अमेरिकी डॉलर है, जिसे बुनियादी ढांचे में

निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सक्षम विनियमन, तेज मंजूरी, सुचारु भूमि अधिग्रहण और जलवायु मंजूरी नीतियों और पर्याप्त बुनियादी ढांचा वित्त की आवश्यकता होगी। लगातार केंद्रीय बजटों में निरंतर बुनियादी ढांचा खर्च और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने से भारत के बुनियादी ढांचे के लक्ष्य को वित्तपोषित करने के लिए माहौल बन रहा है।

उच्च श्रेणी का विनिर्माण आधार विकसित करके नौकरियों के औपचारीकरण को सुगम बनाया जाएगा। भारत ने अपनी विकास यात्रा में विनिर्माण को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया - आज भारत की अर्थव्यवस्था में सेवाओं का हिस्सा दो-तिहाई है जबकि विनिर्माण का योगदान लगभग 17 प्रतिशत है। 1990 के दशक से विनिर्माण की औसत वृद्धि 7 प्रतिशत रही है। 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, विनिर्माण का हिस्सा 2030-31 तक जीवीए का 20 प्रतिशत हो सकता है। यदि विनिर्माण की विकास दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, तो सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण का हिस्सा 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जिससे भारत अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए आगे और पीछे के संबंधों के साथ एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की कगार पर पहुंच जाएगा। विनिर्माण शक्ति के रूप में सफल होने के लिए कुशल श्रम शक्ति का होना आवश्यक है।

भारत के विनिर्माण को वैश्विक बाजारों में स्थान मिलना चाहिए - दुनिया के लिए भारत में विनिर्माण। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत और विविधतापूर्ण विनिर्माण आधार आवश्यक है। भारत के माल और सेवाओं के निर्यात को 768 बिलियन अमेरिकी डॉलर या दुनिया के कुल 2.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक माल और सेवा निर्यात के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक कुल का 5 प्रतिशत करने के लिए तीव्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आईटी और डिजिटल सेवाओं, उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों; उच्च मूल्य वाले पर्यटन; वित्तीय सेवाओं; खुदरा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों के रूप में क्षमता मौजूद है। भारत उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन योजना, निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों, जैसी पहलों के माध्यम से इस निर्यात अभियान के लिए तैयारी कर रहा है; और सूक्ष्म, लघु और मध्यम

³ व्हीबॉक्स : भारत कौशल रिपोर्ट 2024. https://wheebox.com/assets/pdf/ISR_Report_2024.pdf

उद्यमों (एमएसएमई) की निर्यात क्षमता का समर्थन कर रहा है। भारत में स्थापित वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) पहले से ही इन अंतर्निहित शक्तियों का दोहन कर रहे हैं। वे पहले से ही भारत के कार्यबल का लाभ उठा रहे हैं, उत्पाद नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, अगली पीढ़ी की बौद्धिक संपदा (आईपी) बना रहे हैं और डिजिटलीकरण पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत एक मजबूत विनिर्माण आधार द्वारा समर्थित निर्यात शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसका स्वाभाविक परिणाम भारतीय रुपये का पूर्ण अंतरराष्ट्रीयकरण होगा। कई कारक पहले से ही मौजूद हैं। भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे बड़े हैं और भारत विप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता है। भारतीय रुपया ऑनशोर की तुलना में तीन गुना अधिक ऑफशोर ट्रेड करता है। भारत एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान व्यवस्था का विस्तार कर रहा है और भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है। गहरे और तरल वित्तीय बाजार विकसित हो रहे हैं। गुजरात के गिफ्ट शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र एक संपन्न वित्तीय परितंत्र के साथ वैश्विक वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभर रहा है। समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर नीतिगत जोर भी आईएनआर के अंतरराष्ट्रीय होने के लिए सकारात्मक है।

आखिरी चुनौती जिस पर मैं बात करूंगा, वह है धारणीय विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हरा-भरा बनाना। इसमें जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करना शामिल है। जलवायु परिवर्तन हम पर हावी हो रहा है, जिससे ग्रह और मानवता खतरे में पड़ रहे हैं। यह वैश्विक स्तर पर खतरनाक पैमाने और गति से प्रकट हो रहा है। यह आजीविका और बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रहा है और स्वास्थ्य, भोजन, ऊर्जा और जल सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। जलवायु संबंधी आपदाएँ अधिक बार और दुनिया भर में हो रही हैं। वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष साबित हुआ। 2024 में, भारत अपनी सबसे खराब गर्मी और जंगल की आग का सामना कर रहा है। बेंगलुरु जल संकट का सामना कर रहा है। जलाशय

सूख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मौसम एजेंसियां ला नीना के कारण इस मानसून के मौसम में बाढ़ की भविष्यवाणी कर रही हैं। हम अब और प्रतिरक्षित या निष्क्रिय नहीं रह सकते।

2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिज 26 (सीओपी26) में, 2030 तक पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में शामिल हैं: (i) 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता; (ii) 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा वाला ऊर्जा मिश्रण; (iii) कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करना; (iv) अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना; और (v) 2070 तक निवल शून्य प्राप्त करना। यह अनुमान लगाया गया है कि तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पहुंच के साथ-साथ 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

मैंने जिन अंतर्निहित शक्तियों का वर्णन किया है तथा अपने आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्प को देखते हुए, यह कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में प्रवेश करेगा तथा 2048 तक नहीं, बल्कि 2031 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तथा 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

इस संदर्भ में मौद्रिक नीति की क्या भूमिका है? मौद्रिक नीति का मुख्य कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनना है। समग्र मांग के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की उभरती हुई उत्पादक क्षमता के साथ व्यापक संरक्षण सुनिश्चित हो सके। मूल्य स्थिरता वह सर्वोत्तम योगदान है जो मौद्रिक नीति अगले कुछ दशकों में संवृद्धि के आकांक्षी पथ की नींव को मजबूत करने के लिए कर सकती है। भारत में मुद्रास्फीति के गठन को वैश्विक मुद्रास्फीति के साथ अभिसरण की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है ताकि रुपये का आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों संरक्षित रहें। यह रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण और कल की दुनिया के आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने के लिए जमीन तैयार करेगा।